

पत्रकार वार्ता

3 दिसम्बर 2014

दिसम्बर 84 के भोपाल में यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों के पाँच संगठनों ने आज गैस काण्ड की 30 वीं बरसी के उपलक्ष्य में आयोजित रैली में दुनिया भर के इंसानों से अपील की कि वे भोपाल में जारी हादसों के अंत के लिए उनके ऊपर दबाव डालें जो इन हादसों के लिए ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने अपने समर्थकों से यूनियन कार्बाइड और उसके सौ प्रतिशत मालिक डाव केमिकल पर दबाव बनाने की अपील की ताकि ये कम्पनियाँ भोपाल में जारी इंसानी बर्दाहली के लिए अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए सुधार करे और 2024 के पहले इस त्रासदी का अंत हो सके।

संगठनों ने कहा की भारत और अमरीका की सरकारें भी विश्व के भीषणतम औद्योगिक हादसे की वजह से भोपाल में जारी त्रासदी के प्रति लापरवही बरतने के लिए ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने दोनों सरकारों को आम इंसानों के ज़िन्दगी और सेहत से ज़्यादा कंपनियों के हितों की रक्षा करने का आरोप लगाया और यह माँग की कि सरकारें आत्मचिंतन और सुधार करें ताकि त्रासदी का अंत हो सके।

आज अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा को भेजे गए एक चिट्ठी में पीड़ितों के संगठनों ने यह माँग की है की अमरीकी सरकार भोपाल में जारी हादसों और पीड़ितों पर किए गए अन्याय के लिए अपनी केन्द्रिय भूमिका को स्वीकार करे।

भोपाल गैस पीड़ित स्टेशनरी कर्मचारी संघ की अध्यक्ष रशीदा बी ने कहा की वीकिलीक्स के दस्तावेज यह दर्शाते हैं की अमरीका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट हेनरी किसिंजर ने भोपाल में हादसे के लिए ज़िम्मेदार मिथाइल आइसोसायानेट कारखाने के लिए लोन जुटाया था। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत प्रधानमंत्री के दफ्तर से प्राप्त एक चिट्ठी के हवाले से यह कहा कि किसिंजर ने इस बात के लिए राजीव गाँधी पर दबाव डाला था ताकि यूनियन कार्बाइड कम मुआवजा देकर मामले से पल्ला झाड सके।

“ओबामा ने मेक्सिको की खाड़ी में हुए तेल रिसन की दुर्घटना के लिए ब्रिटिश पेट्रोलीयम कंपनी से 2000 करोड़ डॉलर लिया था। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि इस दुर्घटना के मुकाबले 2000 गुना ज़्यादा मौत ढाने के लिए इस राशि का एक क्षुद्र अंश देकर दो अमरीकी कंपनियों के निकल जाने को उनका ज़मीर कैसे बर्दाश्त करता है” कहते हैं भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव।

भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा के नवाब खान ने कहा की केंद्र सरकार द्वारा गैस काण्ड के बाद की पीढी के बारे में बरती जा रही उदासीनता भोपाल गैस पीड़ितों के तरफ उसकी लापरवाही का सबसे ज्वलंत उदाहरण है | “सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 3 अक्तूबर 1991 के आदेश में केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया था की गैस काण्ड के बाद पैदा हुए कम से कम एक लाख बच्चों को चिकित्सीय बीमा की सुविधा दी जाय, पर आज तक एक भी बच्चे को यह सुविधा नहीं मिल पाई है” उन्होंने कहा |

“सर्वोच्च न्यायालय और भारत सरकार दोनों यह मानते हैं की पचास हज़ार से ज़्यादा लोग जो 22 साल तक अपने पीने के पानी में खतरनाक ज़हर पीते रहे हैं पर आज तक प्रदूषित भूजल से पीड़ित इंसानों के इलाज की कोई सुविधा नहीं मिल पाई है | प्रदूषित भूजल पीड़ित आबादी में जन्मजात विकलांगता के साथ पैदा हो रहे सैंकड़ों बच्चों के पुनर्वास के लिए भी सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया है” कहती हैं डाव कार्बाइड के खिलाफ बच्चे संगठन की साफरीन खान |

भोपाल ग्रुप फॉर इन्फार्मेशन एंड एक्शन की रचना ढींगरा ने बताया की पाँचों संगठनों के नेता बहुत जल्दी केंद्र सरकार और अमरीकी कंपनियों से अतिरिक्त मुआवजा लेने के सम्बन्ध में रसायन मंत्री द्वारा हाल में दिए गए आश्वासनों पर मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत करने जाएँगे | पाँच गैस पीड़ित महिलाओं के साथ पिछले महीने रचना नई दिल्ली में निर्जला अनशन पर बैठी थी और उन्हें मंत्री के तरफ से यह आश्वासन प्राप्त हुआ था की हादसे की वजह से हुई मौतों और बीमारियों के आंकड़े वैज्ञानिक आधार पर सुधारे जाएँगे | “ हमें पूरा यकीन है की यदि मंत्री जी अपने आश्वासन पर अमल करते हैं तो अपने वाजिब हक़ से वंचित बहुसंख्यक गैस पीड़ितों को एक लाख रूपए का अतिरिक्त मुआवजा मिल सकेगा और सरकार अमरीकी कंपनियों से हर पीड़ित के लिए कम से कम छ लाख मुआवजे का दावा कर सकेगी |

रशीदा बी भोपाल गैस पीड़ित स्टेशनरी कर्मचारी संघ 9425688215	बालकृष्ण नामदेव भोपाल गैस पीड़ित निराश्रित पेंशनभोगी संघर्ष मोर्चा 9826345423	नवाब खान भोपाल गैस पीड़ित महिला पुरुष संघर्ष मोर्चा 8718035409	रचना ढींगरा सतीनाथ , षडंगी भोपाल ग्रुप फॉर इन्फार्मेशन एंड एक्शन 9826167369	साफरीन खान डाव कार्बाइड के- खिलाफ बच्चे
---	---	--	---	---